रेलवे द्वारा केवल उन्हीं व्यक्तियों को मुआवजा दिया जाता है जो रेल दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं/घायल होते है।

(घ) पिछले 8 माह के दौरान (मई, 1998 से दिसम्बर, 1998 तक) चलती रेलों में हुई लूटपाट/डकैती की घटनाओं से संबंधित उपलब्ध सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

पिछले 8 माह (मई 98 से दिसम्बर 98 तक) के दौरान चलती रेलों में हुई लूटपाट/डकैती की घटनाएं

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	चलती रेलों में लूटपाट	चलती रेलों में डकैती
आन्ध्र प्रदेश	4	1
अ. और न. द्वीपसमूह	कोई रेलवे नहीं	
अरूणाचल प्रदेश	कोई रेलवे नहीं	
असम	10	6
बिहार	प्राप्त नहीं हुई	
चंडीगढ़	0	0
दमन और द्वीप	कोई रेलवे नहीं	
दा. और न. हवेली	कोई रेलवे नहीं	
दिल्ली	प्राप्त नहीं हुई	
गोवा	0	0
गुजरात	19	2
हरियाणा	0	1
हिमाचल प्रदेश	0	0
जम्मू और कश्मीर	0	0
कर्नाटक	0	0
केरल	0	0
लक्ष्यद्वीप	कोई रेलवे नहीं	
महाराष्ट्र	17	9
मध्य प्रदेश	17	0
मेघालय	कोई रेलवे नहीं	
मिजोरम	0	0
मणिपुर	0	0
नागालैंड	0	0
उड़ीसा	7	0
पांडिचेरी	0	0
पंजाब	0	0
राजस्थान	10	0
सिक्किम	कोई रेलवे नहीं	
तमिलनाडु	6	0
त्रिपुरा	0	0
उत्तर प्रदेश	27	7
पश्चिम बंगाल	28	16
कुल	145	42

कानून और व्यवस्था की बिगड़ती हुई स्थिति में बिहार पुलिस की भागीदारी

1599. **श्रीमती मालती शर्मा:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) क्या बिहार की बिगड़ती हुई कानून और व्यवस्था की स्थिति के लिए बिना पुलिस काफी हद तक जिम्मेदार है; और क्या यह निर्दोष लोगों को झूठे मामलों में फसाने और उन्हें आकारण उत्पीड़ित करने की आदी हो गई है;

(ख) यदि हां, तो सरकार को नालंदा थाने, जिला नालंदा (बिहार) के पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध इस प्रकार के कितने मामलों की सूचना मिली है;

(ग) क्या सरकार का ध्यान पटना से प्रकाशित होने वाले 20 अगस्त, 1998 के "आज" से "नालन्दा के पुलिस अधिकारी की धांधली की सुनवाई अदालत में" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी और संबंधित पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

Separate Human Rights Commission for the North-East

1600. SHRI PARAG CHALIHA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it has been demanded that a separate Human Rights Commission for North-Eastern Region should be set up; and

(b) if so, the reaction of Government thereto?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI L.K. ADVANI): (a) and (b) The Central Government has been pursuing the matter of setting up State Human Rights Commissions with the State Governments. In response to this,